TYTLER): (a) Highway-wise accident statistics are not collected.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Compensation to road accident victims is payable under section 140, 161 and 163A of Motor Vehicles Act, 1988. The amount of compensation is to be assessed and claimed by the heirs of the victims themselves from the respective insurance companies through Motor Accident claims tribunals.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

मध्य प्रदेश में चालू रेल परियोजनाओं को पूरा किया जाना

*152. **श्री राघवजी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय पश्चिम और मध्य रेलवे के अधीन क्रियान्वित की जा रही चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब आरम्भ किया गया था और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है;

(घ) क्या राज्य में रेल विकास की दर भारतीय रेल विकास की दर से बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) ब्यौरा इस प्रकार है:

परियोजना का नाम	प्रारंभ करने का वर्ष	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1. नई लाइनें		
1. गुना-इटावा बड़ी लाइन	1985-86	नौवीं योजना
2. दाहोद बड़ी लाइन के रास्ते गोधरा-इन्दौर	1989-90	जिस कार्य को संसाधनों की तंगी के कारण रोक दिया गया था उसे हाल ही में पुनः शुरू किया गया है। परियोजना को नौवीं योजनावधि में पूरा करने की आशा है।
2. आमाप परिवर्तन		
1. नीमच-रतलाम	1993-94	1996-97
2. परसिया-छिंदवाडा	1994-95	1995-96
3. दोहरीकरण		
1. 3 इकहरी लाइन वाले सैक्शनों का दोहरीकरण, अनास पुल, पंचपिपलिया सुरंग तथा माहीपुल	1986-87	31.12.95
2. बोलई-अकोदिया तथा पिरूमरोद बेरछा	1989-90	30.6.96
3. बैरागढ़-फांदा	1989-90	30.9.95
4. कालापीपल-फांदा	1990-91	कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
5. मकसी-बैरागढ़	1992-93	4 ब्लाक खंडों पर कार्य हाल ही में पुनः शुरू किया गया है। परियोजना के नौवीं योजनावधि में पूरा हो जाने की आशा है।
6. चंबल पुल सहित हेतमपुर-घेर इकहरी लाइन	1990-91	1997-98
4. विद्युतीकरण	कोई नहीं	

(ग) और (घ) जी, नहीं। रेलें, मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रेल अवसंरचना की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही हैं। सतना-रीवा नई लाइन, जिसे 1993 में पूरा किया गया था, ऐसी ही एक परियोजना है। ऐसी ही अन्य परियोजनाएं, जो इस समय प्रगति पर हैं वे हैं—गुना-इटावा, देवास-मकसी तथा गोधरा-इन्दौर नयी बड़ी लाइनें। रेलों ने इल्लीरजहरा-जगदलपुर तथा विश्रामपुर-अंबिकापुर नई बड़ी लाइनों से संबंधित कार्य को भी रेल बजट-1995-96 में शामिल किया है जो जब पूरी हो जाएगीं तो मध्य प्रदेश के बस्तर तथा सरगुजा जिले जैसे अन्य पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक रेल अवसंरचना की व्यवस्था करेंगी। छिंदवाडा क्षेत्र में परसिया-छिंदवाडा खंड का आमान परिवर्तन कार्य भी शुरू किया गया है तथा इसे 1995-96 में पूरा करने का लक्ष्य है जबकि जबलपुर-गोंदिया खंड के कार्य को, अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से 1995-96 में बिना बारी के कार्य के रूप में करने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

New Projects for Madras Port Trust

2153. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the new projects submitted by the Madras Port Trust;

(b) by when these projects would be implemented;

(c) what is the cost of these projects; and

(d) the money allotted for implementing these projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) The new major projects submitted by Madras Port Trust are as follows:

(i) Construction of one multi-storeyed transit shed by dismantling West Quay transit shed and converting the balance area into storage yard has been sanctioned on 19.6.95 at an estimated cost of Rs. 18.30 crores with the completion period of 30 months from the date of sanction. An amount of Rs. 5.50 crores has been provided in the Annual Plan 1995-96.

(ii) Extension of South Quay and modernisation of East Quay berths at an estimated cost of Rs. 40.34 crores. The completion period will be 42 months after sanction. Rs. 0.10 crores has been allocated in the Annual Plan 1995-96.

(iii) Modernisation of West Quay and Extension of North Quay at an estimated cost of Rs. 41.95 crores. The completion period will be 42 months after sanction. Rs. 2.00 crores has been provided in the Annual Plan 1995-96.

(iv) Further extension of container terminal at an estimated cost of Rs. 195.25 crores and the completion period will be 42 months after sanction. An amount of Rs. 5.00 crores has been provided in the Annual Plan 1995-96.

दिल्ली में पब्लिक कॉल आफिसेज

2154. **श्री गोविन्द राम मिरीः क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के दक्षिण I और दक्षिण II क्षेत्रों के पब्लिक कॉल आफिसेज (पी०सी०ओ० / आई०एस०डी० / एस०टी०डी०) का उनकी संख्या सहित एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है और समाज के किस-किस वर्ग के हित में इन आफिसेज को स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या पब्लिक कॉल आफिसेज का अनुमोदन करते समय संसद सदस्यों की सिफारिश पर भी ध्यान दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो संसद सदस्यों की सिफारिशों और मंत्री जी की पहल पर अनुमोदित किए गए पब्लिक कॉल आफिसेज का ब्यौरा क्या है?